संपादकीय जागरण

सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 5 वि. 2075

परमसत्ता के समक्ष समर्पण ही आध्यात्मिकता है

अयोध्या पर सुनवाई

यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सदियों पुराने अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू होने जा रही है। चूंकि इस मामले की सुनवाई में पहले ही बहुत देर हो चुकी है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि अब अदालती प्रक्रिया में कोई अड़ंगा न लगने पाए। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि कुछ लोग नए सिरे से यह कोशिश कर सकते हैं कि अयोध्या मामले की निर्णायक सुनवाई में देरी हो। इस आशंका का कारण अतीत का अनुभव है। यह किसी से छिपा नहीं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को अपनी प्राथमिकता से बाहर रखा, फिर जब जल्द निपटारे की याचिका पेश की गई तो कुछ अड़ंगेबाज आगे आ गए। उनकी ओर से ऐसी दलीलें दी गईं कि इस मामले की सुनवाई अगले आम चुनाव तक टाल देनी चाहिए। ऐसी दलील देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट को उलझाने की भी कोशिश की। वे एक हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या विवाद की सुनवाई करने के पहले एक ऐसे मामले पर विचार करना पड़ा जिसका अयोध्या के मूल मामले से कोई सीधा लेना-देना न था। इसके चलते अनावश्यक देरी हुई। इस देरी के कारण ही मामले को सुनने वाली पीठ के सदस्यों में फेरबदल हुआ। कम से कम अब तो यह होना ही चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व के इस मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन हो।

यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मसले को जमीन के मालिकाना हक के विवाद के तौर पर देखेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह मूलतः इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले पर विचार करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का जो फैसला दिया था उसका एक आधार अयोध्या ढांचे से मिले पुरातात्विक साक्ष्य थे। अदालतें आस्था के आधार पर फैसले नहीं दे सकतीं, लेकिन वे पुरातात्विक साक्ष्यों पर तो विचार कर ही सकती हैं। अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के आकांक्षी इसीलिए अपना पक्ष मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि विवादित स्थल पर मंदिर होने के ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण हैं। बावजूद इस सबके यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। अच्छा होता कि यह मामला उस तक पहुंचता ही नहीं और आस्था से जुड़े इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जाता। इससे दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का संचार होता और देश ही नहीं दुनिया के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण पेश होता। यह खेद की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। आपसी सहमति से अयोध्या विवाद का न सुलझ पाना देश के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व की विफलता है। यह विफलता इसीलिए मिली, क्योंकि इन सवालों से मुंह चुराया गया कि अयोध्या में बाबर के नाम वाली मस्जिद क्यों बनी और यदि राम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बन सकता तो और कहां बन सकता है? काश राम मंदिर के सवाल पर वोटबैंक की राजनीति न की जाती। हालांकि अब आपसी बातचीत से अयोध्या विवाद का हल निकालने में देर हो गई है, परंतु इस दिशा में पहल अभी भी हो सकती है।

तय हो जवाबदेही

बदायूं के गांव रसूलपुर में दो दिन पहले पटाखा कारखाने में विस्फोट से न केवल आठ लोगों की मौत हो गई, बल्कि छह लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। प्रशासनिक अमला और विभिन्न एजेंसियां जांच में जुट गई हैं तो राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब आतिशबाजी कारखाने में विस्फोट से जन-धन की हानि हुई हो। ऐसी घटनाएं दीपावली के इर्द-गिर्द बढ़ जाती हैं। हर बार जांच और आर्थिक मुआवजे से आगे मामला नहीं बढ़ पाया है। इस बार भी ऐसा ही होगा। कमजोर वर्ग के लोगों को मुआवजा मिलना ही चाहिए लेकिन, क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किये जाते कि यह नौबत ही न आये।

> अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय कर दी जाए तो जान-माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है

सबको पता है, पटाखा निर्माण खतरनाक और संवेदनशील कार्य है। इसके लिए कुछ जरूरी मानक तय किए गए हैं। उन मानकों के पालन की शर्तों पर लाइसेंस भी दिए जाते हैं। लेकिन, कई बार लाइसेंसशुदा कारखानों में हादसे सामने आते हैं तो उससे कहीं ज्यादा गैर लाइसेंसी कारखानों में दुर्घटनाएं होती हैं। अब यदि विभिन्न एजेंसियों ने जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कारखाने में मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा था, तो क्या संबंधित विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। ऐसा होगा यह लगता भी नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी सुनने-देखने में नहीं आया है कि पटाखा कारखाने में विस्फोट पर किसी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई हुई हो। बाद में लकीर पीटने के बजाए यदि अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय कर दी जाए तो जान-माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरी तरह जवाबदेह बनाना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टी-20 टीम से महेंद्र सिंह धौनी की छुट्टी करना सही फैसला है?

आज का सवाल

क्या भारत और जापान मिलकर चीन को कड़ी चुनौती दे सकते हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

निर्णायक साबित होने वाली दोस्ती

ब्रह्मा चेलानी

अगर जापान और भारत अपने रिश्ते में सुरक्षा से संबंधित कुछ ठोस पहलू जोड़ते हैं तो उनकी रणनीतिक साझेदारी एशिया में बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे के लिए रविवार को टोक्यो पहुंच गए हैं। बीते चार वर्षों में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी के साथ यह उनकी 12वीं मुलाकात है। मोदी के आगमन पर एबी उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को नए क्षितिज पर ले जाने का भरोसा जता चुके हैं। इस वार्ता के दौरान दोनों नेता सैन्य साझेदारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं जिसमें दोनों देशों की एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच होगी। एशिया के सबसे संपन्न-समृद्ध लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र उस 'मुक्त एवं खुली हिंद-प्रशांत रणनीति' के अहम हिस्से हैं जिसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में तो एबी ही इस रणनीति के असल शिल्पकार हैं जिसकी अवधारणा उन्होंने औपचारिक रूप से दो साल पहले नैरोबी में अफ्रीकी नेताओं को संबोधित करते हुए सामने रखी थी। आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विधिसम्मत, मुक्त व्यापार, आवाजाही की आजादी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त ढांचा बनाने के लिहाज से जापान और भारत उसकी अहम धुरी हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 'मुक्त एवं स्वतंत्र' क्षेत्र बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन भारत-जापान संबंधों के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है। ट्रंप की हिंद-प्रशांत नीति उनके पूर्ववर्ती ओबामा की एशिया केंद्रित नीति का ही नया रूप है। ओबामा ने 2011 में इसे पेश किया था जिसे बाद में 'एशियाई पुनर्संतुलन' का नाम दिया गया। अमेरिका को लगा कि उसने पश्चिम एशिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया और अब इस नीति को सुधारने की दरकार है। अब अमेरिका अपने दीर्घकालिक हितों के लिए एशिया की अहमियत पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

एशियाई सुरक्षा प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से सामुद्रिक मोर्चे पर ही चल रही है। 'हिंद-प्रशांत' शब्द का बढ़ता चलन भी इसे दर्शाता है जो हिंद और प्रशांत जैसे दो महासागरों के मिलन का भी प्रतीक है। इस क्षेत्र में भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी जोर पकड़ रही है जिसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा और कुछ खतरनाक इलाके शामिल हैं। इस तरह देखें तो वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था की कुंजी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हाथ में ही है। दरअसल हिंद-प्रशांत क्षेत्र को और व्यापक बनाकर अमेरिका एक तरह से चीन की बेल्ट एंट रोड इनिशिएटिव जैसी योजना की काट तलाश रहा है जिसमें चीन का भारी निवेश हिंद महासागर की परिधि में पड़ने वाले देशों में ही हो रहा है। जिबूती में तैयार चीन के पहले विदेशी नौसैनिक अड्डे और मालदीव के कई निर्जन द्वीपों पर उसके काबिज होने के बाद हिंद महासागर भी बीजिंग का भू-सामरिक अखाड़ा बनता जा रहा है। इससे पहले वह दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बनाकर उनका सैन्यीकरण करने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के दूसरे दिन कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इसमें साझेदारी के जरिये नौसैनिक मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने वाला करार भी शामिल है। जापानी और भारतीय सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक यानी सैन्य तंत्र साझेदारी अनुबंध होना है। पहले इसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी एसीएसए का नाम दिया गया था। यह दोनों सेनाओं के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वे कई दांव एक साथ आजमा रही हैं जिनमें त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास भी एक है। इसमें अमेरिकी नौसेना भी शामिल होती है जिसे हिंद और प्रशांत महासागर में अंजाम दिया जाता है।

भारत के साथ एसीएसए करार से हिंद महासागर में जापान की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को स्थायित्व मिलेगा। इसमें जापानी पोतों को भारतीय नौसैनिक ठिकानों पर ईंधन और मरम्मत कराने की सुविधा मिलेगी। वहीं जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षा बल यानी जेएमएसडीएफ को भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसैनिक सुविधाओं की सौगात मिलेगी जो मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी द्वार के काफी नजदीक स्थित है। जापान और चीन का काफी व्यापार और तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। एबी के शासन में सेना पर कई कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों को कुछ नरम बनाया गया है। इससे जापानी नौसेना की भूमिका का दायरा बढ़ा है। अब वह जापानी तटों से दूर भी सक्रियता से संचालन कर सकती है। वास्तव में संयुक्त सैन्य अभ्यास से लेकर सैन्य प्रशिक्षण के जरिये क्षेत्रीय सुरक्षा में भागीदारी को लेकर जापान का नया उत्साह उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू-सामरिक समीकरणों का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है।

भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ भी सैन्य ढांचे वाला अनुबंध किया हुआ है। इन दोनों के भी हिंद और प्रशांत महासागर में अहम सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में जापान के साथ सैन्य ढांचे की साझेदारी वाला करार और व्यापक द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग भारतीय नौसेना को पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी पैठ बनाने में मदद करेगा। भारत और जापान का न तो इतिहास में कोई टकराव रहा है और न ही किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दे पर उनमें असहमति है इस लिहाज से दोनों स्वाभाविक साझेदार के रूप में ही नजर आते हैं जिनके परस्पर हित जुड़े हुए हैं। वास्तव में जापान ही इकलौता ऐसा देश है जिसे भारत के कुछ संवेदनशील इलाकों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति है। इनमें पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। अगर जापान और भारत अपने रिश्ते में सुरक्षा से संबंधित कुछ ठोस पहलू जोड़ते हैं तो उनकी रणनीतिक साझेदारी एशिया में बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है। व्यापार एवं निवेश पर जितना जोर दिया जा रहा है उसे व्यापक रणनीतिक सहयोग के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। भारत में जापान के राजदूत केंजी हीरामत्सू भी कहते हैं कि अब सामरिक भागीदारी को बढ़ाने की दरकार है।

शी चिनफिंग के साथ एबी की हालिया बैठक और अप्रैल में मोदी के साथ बैठक इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकतीं कि भारत और जापान चीन की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह व्यापार, तकनीक एवं अन्य मोर्चों पर ट्रंप का चीन पर दबाव ही है जिसने चिनफिंग को मोदी और एबी जैसे नेताओं से संपर्क करने को विवश किया। चिनफिंग को उम्मीद है कि जब अमेरिका की चीन नीति में बुनियादी रूप से बदलाव हो रहा है तो उसे जापान का वैसा ही साथ मिलेगा जैसे उसने 1989 में थियानमेन चौक पर छात्रों के नरसंहार को लेकर फंसे चीन का दिया था। तब चीन पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने वाला जापान शुरुआती देशों में एक था। चीन के साथ रिश्तों को लेकर अब जापान भी व्यावहारिक नजरिये वाला हो गया है। वहीं भारत भी किसी भ्रम में नहीं है कि चिनफिंग के नेतृत्व में चीन हेकड़ी छोड़कर अच्छा पड़ोसी बनने जा रहा है।

इस परिदृश्य में एबी-मोदी वार्ता कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक अवसर है जिसमें दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, शक्ति स्थायित्व एवं सामुद्रिक सुरक्षा में परस्पर योगदान पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक वाशिंगटन की बात है तो दक्षिण चीन सागर में बदलते हालात से निपटने के लिए उसे स्पष्ट नीति की दरकार है, क्योंकि 'स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए यह बेहद अहम रणनीतिक गलियारा है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

मी टू में हर तबके को मिले अभिव्यक्ति

डॉ. एके वर्मा

मी टू में तमाम गरीब महिलाओं और पुरुषों का शामिल होना शेष है जो यौन दुराचार के आघात को लज्जा के कारण बताते नहीं हैं

देश में 'मी टू' आंदोलन महिला सशक्तीकरण से आगे जाकर महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के विरुद्ध प्रवृत्तियों को न केवल सामाजिक बुराई के रूप में रेखांकित करता है, वरन राजनीतिक, प्रशासकीय और सामाजिक शुचिता के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत का भी द्योतक है। यह आंदोलन नारी के बदलते मनोविज्ञान को दर्शाता है। अब नारी यौन दुराचरण को लेकर अपराधबोध से त्रस्त अंतर्मुखी होने के बजाय उसे समाज के समक्ष उजागर कर उच्छृंखल व्यक्ति को सामाजिक कटघरे में खड़ा करने का साहस करना सीख रही है। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं। जिस देश में नारी लज्जा को ही नारी का आभूषण माना जाता रहा हो वहां यह और भी मुश्किल था। लज्जा के आवरण को तोड़ यौन शोषण के विरुद्ध बिगुल बजाना भारतीय नारी के बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का परिचायक है। इसकी गिरफ्त में कब कौन आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। यह प्रवृत्ति नीचे तक जाएगी जहां राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक प्रदूषण अपने चरम पर है। इसे भारतीय राजनीति और प्रशासन में शुचिता की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जिसके लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन गया है।

लेकिन 'मी टू' की सबसे बड़ी चुनौती है कि यह आंदोलन कहीं नारी बनाम पुरुष न हो जाए। इसका कारण यह कि इसके शिकार उच्च राजनीतिक या प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए पुरुष ही होंगे और वे पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को नारी बनाम पुरुष बना दिया जाए जिससे यह कमजोर पड़ जाए। यह आंदोलन 'यौन शोषण' जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध है। इसमें नारी और पुरुष दोनों को सतर्क रहना होगा। महिलाओं को देखना होगा कि इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक या वित्तीय लाभ के लिए पुरुषों पर बेबुनियाद आरोप न लगाए जाएं और पुरुषों को सतर्क रहना होगा कि स्वार्थी तत्व लैंगिक आधार पर पुरुषों को भड़काकर उन्हें महिलाओं के विरुद्ध लामबंद न कर सकें। यह नारी और पुरुष की यौन शोषण के विरुद्ध साझी लड़ाई है, क्योंकि यौन शोषण का शिकार केवल नारी ही नहीं, पुरुष भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि तमाम बच्चों का बचपन यौन शोषण के भयानक साए में बीतता है। वे अपनी त्रासदी साझा भी नहीं कर पाते और अवसाद के शिकार हो जाते हैं या अपराध की दुनिया का रुख करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए पुरुष समाज को इस आंदोलन में न केवल महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा, बल्कि इसे और व्यापक बनाने की भी कोशिश करनी होगी।

'मी टू' अभी केवल उच्चवर्गीय और कामकाजी महिलाओं तक ही सीमित है। उनमें इतना साहस है कि वे लोकलाज की लक्ष्मण रेखा को लांघकर उस सत्य को उजागर कर रही हैं जो अन्यथा कभी उजागर ही नहीं होता, लेकिन अभी इसमें उच्च मध्यम, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं के एक बहुत बड़े तबके को शरीक होना है जो यौन दुराचार के आघात को लज्जा के आवरण में रखने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी समाज में उन्हें वह आर्थिक मजबूती नहीं मिली है जो उन्हें उस आवरण को तोड़ने का साहस दे सके। जैसे-जैसे महिलाओं की संख्या विभिन्न सेवाओं में बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे यह समस्या और विकराल स्वरूप ग्रहण करती जा रही है। हालांकि कुछ अत्यंत महत्वाकांक्षी महिलाएं नारी स्वतंत्रता की आड़ ले, यौनता को हथियार बनाकर कार्यक्षेत्रों में अन्य महिलाओं से आगे निकलना चाहती हैं। यह स्वाभाविक मानवोचित प्रवृत्तियां हैं, जिसका फिलहाल कोई निदान नहीं। 'मी टू' पुरुष समाज को भी ऐसी महत्वाकांक्षी महिलाओं के इरादों से सतर्क करेगा और उनके मन में यह भय भरेगा कि कहीं आगे चलकर वे 'मी टू' के शिकार न बनें, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि नीचे तक संदेश जाए कि संपूर्ण समाज को नारियों के सम्मान और सुरक्षा की चिंता है।

बहरहाल इस आंदोलन को और आगे ले जाने की जरूरत है। इसमें घर की दहलीज के अंदर अपनों द्वारा बाल्यकाल और किशोरावस्था में स्त्रियों के यौन शोषण से बात शुरू होनी चाहिए। साथ ही पड़ोस एवं मोहल्ले के अनेक लोगों द्वारा हर उम्र की महिलाओं से जो छेड़छाड़ और अश्लील व्यवहार प्रायः किया जाता है, उसे कैसे 'पब्लिक-स्पेस' के कटघरे में लाया जाए? असंगठित तथा संगठित निजी क्षेत्र में भी असंख्य तरीकों से महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, क्या उसे 'मी टू' आंदोलन की परिधि में नहीं लाया जा सकता?

जिस देश में सामाजिक संस्कृति का दार्शनिक आधार नारी-पुरुष समानता हो, ईश्वर को 'अर्द्धनारीश्वर' स्वरूप से व्यक्त किया गया हो, जहां शक्ति के सभी प्रतीक नारी हों, जहां हिंदू धर्म में राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा और शिव के साथ पार्वती की आराधना होती हो, ऐसे समाज में नारी द्वारा अशक्त, असुरक्षित और अपमानित होने की अनुभूति क्या एक विरोधाभास को नहीं दर्शाती? फिर हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में नारी के 'काम-स्वरूप' की उपेक्षा भी नहीं की गई। उर्वशी, रंभा, मेनका और तमाम अप्सराओं की कामुक प्रस्तुतियों से लेकर अजंता-एलोरा और खजुराहो की कलात्मक काम प्रस्तुतियां इस बात की गवाह हैं कि स्त्री के दोनों रूप हमारे समाज में एक साथ रहे हैं। हमें नारी के इन दोनों ही रूपों को स्वीकार करना होगा। भारत तो वह देश है जहां नारी के पत्नी रूप सीता और सावित्री के साथ-साथ उसके प्रेयसी या प्रेमिका स्वरूप राधा के प्रति भी सामाजिक स्वीकृति और आदर की विपुलता रही है। तो फिर समाज में नारी के प्रति ऐसी दृष्टिकोणमूलक विसंगति आ कैसे गई? अपवादस्वरूप तो हर युग में ही नारी के सम्मान के प्रति धृष्टता के उदाहरण हैं। जैसे-त्रेता में रावण द्वारा सीता और द्वापर में कौरवों द्वारा द्रौपदी के सम्मान के प्रति धृष्टता सर्वविदित है, लेकिन महाभारत और रामायण दोनों में यही संदेश है कि ऐसी धृष्टता नाश का कारण बनती है।

अच्छी बात यह है कि 'मी टू' मुहिम सामाजिक बुराई और अनैतिकता के खिलाफ नैतिकता और जनमत के हथियार से लड़ने की कोशिश कर रही है। प्रायः सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए कानून का सहारा लेने का प्रयास किया जाता है जो कभी सफल नहीं होता। बाल विवाह से लेकर दहेज निरोधक आदि अनेक कानूनों का हश्र हम सभी जानते हैं। 'मी टू' द्वारा भारतीय महिलाओं ने जो मार्ग दिखाया है, उससे न केवल नारियों के यौन उत्पीड़न पर लगाम लगेगी और बड़े पदों पर बैठे यौन अपराधी दंडित होंगे, बल्कि इससे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को एक खुली हवा में पुरुष समाज के साथ सांस लेने का मौका मिलेगा जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक शुचिता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

(लेखक सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का भटकाव

कहते हैं कि 'मनुष्य' शब्द का प्रादुर्भाव मन से हुआ है और यही कारण है कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास की जड़ें उसके मन में ही अवस्थित होती हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि अंग्रेजी शब्द 'मैन' की उत्पत्ति भी मन से हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में मन की महत्ता किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से की गई है जो कि समस्त प्रोग्रामिंग के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर की तमाम गतिविधियां भी अपना पोषण मन से ही प्राप्त करती हैं। यहां तक कि शरीर की तमाम व्याधियों का मूल कारण भी मन को ही माना जाता है। यदि मन को स्वस्थ कर लिया जाए तो शरीर रोगमुक्त हो जाता है और संपूर्ण व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का निखार महसूस किया जाता है।

सदा अप्रसन्न तथा दुखी रहने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाता है। पतंजलि के योग विज्ञान में सांसों के नियंत्रण को मन पर नियंत्रण तथा मन को स्वस्थ रखने का सर्वसिद्ध तथा अचूक समाधान माना गया है। लेकिन अहम प्रश्न यह उठता है कि आखिर मन भटकता ही क्यों है? मन दुखी ही क्यों होता है? वस्तुतः इच्छाएं मानव मनरूपी नौका की पतवार की तरह होती हैं। मन के भटकाव को संयमित करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं की गति को संयमित करने की जरूरत है। इच्छाओं की पहचान करने की जरूरत है तथा वैसी ही इच्छाओं को मन में जगह देने की आवश्यकता है जिनकी अनुपस्थिति में जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि इस क्रिया को ही कर लें तो कई मुश्किलों को मात दी जा सकती है।

बुद्ध से लेकर ईसा तथा महावीर से लेकर गुरुनानक, ईश्वर के इन सभी देवदूतों ने लिप्साओं और इच्छाओं को ही जीवन में दुख का कारण बताया है। मन के भटकाव पर दमन में ही सच्चे सुख तथा अलौकिक परमानंद का रहस्य छुपा हुआ है। सनातन से ही मौन व्रत के द्वारा मन के शुद्धिकरण का विज्ञान सरल तथा सहज विधा के रूप में हमारे आर्ष जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। संयमित और स्थिर मन से इतर जीवन में परम शांति तथा चिर स्वास्थ्य की खोज महज एक मृगतृष्णा है, जिससे बच कर रहने की जरूरत है।

श्रीप्रकाश शर्मा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सीबीआइ की विश्वसनीयता

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'सीबीआइ की साख बचाने की चुनौती' में देश की अति विश्वसनीय मानी जाने वाली जांच एजेंसी की साख को लेकर जो बात की है, वह केवल दो वरिष्ठ सीबीआइ अधिकारियों के बीच की आपसी कहा-सुनी न होकर एक दूसरे पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप-प्रत्यारोप हैं, जिससे सीबीआइ की अपनी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इससे मोदी सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक था, अतः उसने आनन-फानन में इन दोनों अधिकारियों को कार्य से विरत करने का फैसला लेकर सीबीआइ की साख को बचाने का काम किया। इस पर यदि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे किसी और नजरिये से देखकर होहल्ला मचा रही है तो यह सीबीआइ को लेकर की जाने वाली एक दूसरी तरह की विकृत राजनीति है, जिसमें यहां तक कहा जा रहा है कि सीबीआइ राफेल सौदे की जांच करने वाली थी इसलिए मोदी सरकार ने जानबूझकर यह बखेड़ा खड़ा किया है। जबकि सब जानते हैं कि राष्ट्रहितैषी राफेल विमान सौदे पर संसद से सड़क तक होने वाली राजनीतिक चर्चा और बयानबाजी में ऐसा कुछ भी निकलकर नहीं आया जो मोदी सरकार को चोर और बेईमान साबित कर सके। बावजूद इसके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बार-बार यह कहना कि राफेल सौदे में मोदी पकड़े जाएंगे तथा सीबीआइ इसकी जांच करने वाली है, मोदी सरकार के विरुद्ध झूठ का बाजार गर्म करना भर है। यदि राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार ने कुछ अनुचित किया है और उसके पर्याप्त सुबूत कांग्रेस के पास हैं तो उसे सीबीआइ जांच का इंतजार किए बिना अभी तक केंद्र सरकार को अभियुक्त बनाकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर देना चाहिए था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी न होने से वह अब आम जनता को भरमाने के लिए झूठ का सहारा लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होने की नाकाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस की यह दूषित राजनीति राफेल विमान के साफ-सुथरे सौदे को दागदार बनाने के साथ-साथ इस प्रकरण में सीबीआइ को घसीटकर उसकी विश्वसनीयता को भी प्रश्नांकित कर रही है जो उचित नहीं है।

डॉ. विष्णु प्रकाश पाण्डेय, अलीगढ़

अंधविश्वास में विरोध

सबरीमाला मंदिर पर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन लोग न्यायालय के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महिलाएं भी कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही हैं। हालांकि, न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस कुप्रथा को समाप्त कर, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का आदेश दिया था, परंतु अंधविश्वास के वशीभूत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि जहां महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, वहां महिलाएं न्यायालय के फैसले का विरोध क्यों कर रही हैं?

श्री कृष्ण, लोनी, गाजियाबाद

बढ़ती जनसंख्या

जनसंख्या और बेरोजगारी का फूलता गुब्बारा अनेक समस्याओं की जड़ है। ताज्जुब की बात है कि कोई भी पार्टी इस पर कुछ नहीं करना चाहती। पार्टियां शायद अपने वोट बैंक के लालच में ही इसे अपने पक्ष में मानती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रोजगार और अन्य सुविधाओं से सीधे जोड़कर इसे आसानी से काबू किया जा सकता है, बशर्ते सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत हो। यदि जनसंख्या व बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं किया गया तो भयावह स्थिति हो सकती है।

वेद मामूरपुर, नरेला

दुर्बल और असहाय भागीरथी !

पुराणों के अनुसार गंगा जी का धरती पर आना त्याग और हठ की अद्भुत घटना है। जिस गंगा के विकराल प्रवाह को रोकने के लिए शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ीं उसी की अविरलता की खातिर एक संत ने अपने प्राण त्याग दिए। पुनः अवतरित हो जाओ भगीरथ! देख लो स्वर्ग से धरती पर उतरी तुम्हारी भागीरथी कितनी दुर्बल और असहाय हो चुकी है। विशाल बांधों ने पहले अविरलता रोकी फिर विकास के ध्वजवाहकों ने शहरों, कस्बों और कारखानों के कचरों को गंगा में डाल दिया। बालू माफिया ने बड़ी बेरहमी से गंगा मैया का कलेजा छलनी किया है तो हमारी आस्था की डुबकी ने भी गंगा को निष्कलंक नहीं छोड़ा है। हिमालय से आती अविरल अमृतधारा को पग-पग पर रोक कर शायद हमने ही विष बना दिया है। जिस पवित्र नदी में पानी की जगह जहर बहता हो उसकी पवित्रता तो दूर, अस्तित्व बचाना कठिन हो जाएगा। निर्मल गंगा के सपने दिखाती सरकार की नीयत भले ही साफ हो मगर वह नीति कहां है जो गंगा को साफ करे।

mkmishra|5@yahoo.in

मजबूत सरकार कैसे?

देश की मजबूती और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए मजबूत सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन विडंबना है कि आज जो मौजूदा राजनीतिक वातावरण है वह मजबूत सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है। जब तक हिंदू -मुस्लिम, आरक्षण, जाति पाति जैसा माहौल रहेगा मजबूत सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मजबूत सरकार के मायने होते हैं, देश में बेहतर व सख्त कानून व्यवस्था। कोई भाई-भतीजा वाद नहीं। लेकिन वर्तमान में कोई भी दल इन बुराइयों से अछूता नहीं है। आखिर मजबूत सरकार कौन देगा?

hemahariupadhyay@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

श्रीलंका में नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में लोग भारत और चीन को लेकर कड़ियां जोड़ने लगे हैं। तमाम स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की वजह से भी ऐसा हुआ है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है।
मीरा श्रीनिवासन@Meerasrini

वेस्टइंडीज के खिलाफ पुणे वनडे मैच में पहले तो एक शानदार कैच और उसके बाद नायाब स्टंपिंग से एमएस धौनी ने दिखा दिया कि आखिर विश्व कप की टीम में उनकी क्यों जरूरत है? वह केवल घरेलू क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करें। फिटनेस और विकेट के पीछे उनका प्रदर्शन अब भी आला दर्जे का है।
बोरिया मजूमदार@BoriaMajumdar

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा विभाजन के लिए भारत को बराबर कसूरवार करार देना सही नहीं है। उन्हें अबुल कलाम आजाद की किताब 'इंडिया विंस फ्रीडम' पढ़नी चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा कि लेडी माउंटबेटन ने विभाजन के लिए नेहरू को प्रभावित किया। अगर पटेल पीएम होते तब शायद अलग तस्वीर होती।
एस गुरुमूर्ति @sgurumurthy

सब-सहारा अफ्रीकी देशों में अभी भी 60 .9 करोड़ लोगों तक बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उनके लिए अक्षय ऊर्जा ही एक समाधान हो सकती है।
एंटोनियो गुतेरस@antonioguterres

जनपथ

साधा जाय नितीश को सीटें कर लीं हाफ,
गठबंधन का रास्ता हुआ इस तरह साफ।
हुआ इस तरह साफ चलेगी अब तैयारी,
जब नीयत हो साफ तभी निभती है यारी।
उधर महागठजोड़ बीच है सत्तर बाधा,
मेढक तौलें रोज लक्ष्य जाए ना साधा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 104